



2026:AHC:58442

इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

बी.एन.एस.एस. कि धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 11194/2026

दिनेश चंद्र गुप्ता

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : संत राम निगम, नितिन द्विवेदी, रामा कांत यादव

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 73

माननीय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।
2. धारा 528 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत वर्तमान आवेदन, दिनांक 14.06.2024 के समन आदेश, दिनांक 22.08.2025 के गैर-जमानती वारंट के साथ-साथ वाद संख्या 7635 वर्ष 2024 (एम/एस बी.पी. ऑयल मिल्स लिमिटेड बनाम एम/एस जय माँ शारदा ट्रेडर्स एवं अन्य), धारा 138 एन.आई. अधिनियम, थाना हरी पर्वत, जनपद आगरा के अंतर्गत, अपर न्यायालय-I, आगरा में लंबित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि पक्षकारों के मध्य धन संबंधी विवाद है तथा प्रतिपक्षी संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध धारा 138 एन.आई. अधिनियम के अंतर्गत एक शिकायत दर्ज की है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि चूँकि धन

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के भुगतान को लेकर विवाद है, अतः समझौते के माध्यम से विवाद के सौहार्दपूर्ण निपटारे की पूरी संभावना संभावना है।

4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **दामोदर एस. प्रभु बनाम सैयद बाबालाल एच., 2010 (5) SCC 663** में दिए गए निर्णय पर भरोसा जताया है। प्रासंगिक पैराग्राफ संख्या 17, 18 और 19 नीचे उद्धृत किए गए हैं:-

"17. हाल ही में प्रकाशित एक टिप्पणी में, अधिनियम की धारा 138 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई हैं [उद्धृत: अरुण मोहन, 'सम थॉट्स टुवर्ड्स लॉ रिफॉर्म्स ऑन द टॉपिक ऑफ सेक्शन 138, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट-टैकलिंग एन एवलांच ऑफ केसेस' (नई दिल्ली: यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, 2009) पेज 5 पर]:

"...अपराध के अन्य रूपों के विपरीत, यहाँ सज़ा (जहाँ तक शिकायतकर्ता का संबंध है) बदला लेने का ज़रिया नहीं है, बल्कि यह ज़्यादातर पैसे का भुगतान सुनिश्चित करने का एक माध्यम है। शिकायतकर्ता की मुख्य दिलचस्पी चेक जारी करने वाले को जेल में देखने के बजाय, अपने पैसे वापस पाने में होती है। जेल की धमकी केवल पैसे की वसूली सुनिश्चित करने का एक तरीका है। दूसरी ओर, यदि आरोपी जेल की सज़ा काटने को तैयार हो जाता है, तो चेक धारक के पास राहत के तौर पर बहुत कम विकल्प बचते हैं।"

अगर हम एक तरफ उन शिकायतों की संख्या की जाँच करें जो अंतिम फ़ैसले से पहले ही 'समझौते' या 'सुलह' के ज़रिए सुलझा ली गईं, और दूसरी तरफ उन मामलों को देखें जो फ़ैसले और सज़ा तक पहुँचे, तो हम पाएँगे कि ज़्यादातर मामले सुलझा लिए गए थे और बहुत ही कम मामले आगे बढ़े।"

18. यह बिल्कुल स्पष्ट है कि चेक के अनादरण के अपराध के संबंध में, उपचार के दंडात्मक पहलू की तुलना में उसके क्षतिपूर्ति वाले पहलू को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विद्वान अटॉर्नी जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को भी कुछ हद तक समर्थन प्राप्त है कि चेक बाउंस के अधिकांश मामले वास्तव में कंपाउंडिंग के माध्यम से निपटाए या सुलझाए जा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रहे हैं; हालाँकि, ऐसा मुकदमेबाजी के बाद के चरणों में होता है, जिससे न्याय मिलने में अनावश्यक देरी होती है। यहाँ समस्या मुकदमों में शामिल पक्षों की उस प्रवृत्ति में निहित है, जिसके तहत वे अपने विवाद को सुलझाने के लिए कंपाउंडिंग का विकल्प काफी देर से चुनते हैं।"

19. जैसा कि पहले बताया गया है, विद्वान अटॉर्नी जनरल का यह कहना है कि वैधानिक मार्गदर्शन के आभाव के कारण, पक्षकार कंपाउंडिंग समझौते को अंतिम उपाय के तौर पर चुन रहे हैं, न कि जैसे ही मजिस्ट्रेट शिकायतों का संज्ञान लेते हैं, तभी इसे चुन लेते हैं। इस तरह के व्यवहार का एक कारण यह हो सकता है कि आरोपी व्यक्ति मुकदमेबाजी के विभिन्न चरणों से गुज़रने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं, और फिर समझौते का रास्ता तभी चुनते हैं जब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचता। हालाँकि, मुकदमेबाजी करने वालों के नज़रिए से इस तरह के व्यवहार को तर्कसंगत माना जा सकता है, लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि कंपाउंडिंग चुनने में होने वाली अनावश्यक देरी, विभिन्न स्तरों पर अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को बढ़ाने का कारण बनती है। यदि आरोपी मुकदमेबाजी के बाद के चरण में अपराध की कंपाउंडिंग के माध्यम से समझौता या सुलह करने को तैयार होता है, तो यह आम तौर पर इस बात का संकेत होता है कि शिकायतकर्ता के मामले में कुछ दम है। ऐसे मामलों में, यह बेहतर होगा यदि पक्षकार मुकदमेबाजी के शुरुआती चरणों में ही कंपाउंडिंग का विकल्प चुन लें। हालाँकि, यदि आरोपी के पास कोई वैध बचाव है जैसे कि गलती, जालसाज़ी, या ज़बरदस्ती, और अन्य आधार—तो इस मामले पर निर्दिष्ट मंचों के माध्यम से मुकदमा चलाया जा सकता है।"

5. जैसा कि अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया है, यह निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्त आज से एक माह की अवधि के भीतर अपने अधिवक्ता के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो और समझौते के माध्यम से अपराध के कंपाउंडिंग हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करे तथा चेक राशि का 10% जमा कर सकता है। ऐसा आवेदन किए जाने पर, संबंधित न्यायालय इस संबंध में विधि के अनुसार उचित कदम उठा सकता है और अभियुक्त को इस दिशा में प्रयास करने के लिए आगे अवसर प्रदान करेगा, जो आज से

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिकतम चार माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तत्पश्चात, न्यायालय आज से पांच माह की अवधि के भीतर, विशेष रूप से **दामोदर एस. प्रभु** (उपरोक्त) के मामले में शीर्ष अदालत द्वारा प्रतिपादित विधि को ध्यान में रखते हुए आवश्यक आदेश पारित करेगा।

6. यदि आवेदक समझौते के माध्यम से अपराध के कंपाउंडिंग हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो उसे उपस्थित होकर विचारण का सामना करना होगा तथा न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध विधि के अनुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगा और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु विधि द्वारा अनुमत सभी आवश्यक कदम एवं उपाय करेगा।

7. उपर्युक्त पाँच माह की अवधि के दौरान अथवा आवेदन के आलोक में पारित निर्णय तक, जो भी पहले हो, अभियुक्त के विरुद्ध कोई दमनात्मक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

8. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश केवल उस अभियुक्त के संबंध में पारित किया गया है, जिसकी ओर से यह आवेदन इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

9. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ यह आवेदन **निस्तारित** किया जाता है।

20 मार्च, 2026

(दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)